जिसके पास
अच्छा दोस्त है
उसे दर्पण की जरूरत
नहीं।

– अज्ञात

झारखंड का जनादेश

झारखंड के आदिवासियों में रघुबर सरकार की नीतियों को लेकर गुस्सा था। उनकी हजारों एकड़ जमीन एक पूंजीपति घराने को पावर प्लांट लगाने के लिए दी गई और उनके विरोध को कुचल दिया गया।

प्रमोद वर्मा

झारखंड का जनादेश न सिर्फ स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय सवालों को लेकर भी जमीनी स्तर पर व्याप्त गहरे असंतोष की अभिव्यक्ति है। बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति के अनुरूप अन्य राज्यों की तरह यहां भी केंद्र सरकार के प्रमुख फैसलों पर वोट मांगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 9–9 चुनावी रैलियां करके राममंदिर, अनुच्छेद 370, तीन तलाक कानून, एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर चर्चा की। हिंदुत्व की लहर चलाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार में उतारा गया।

एनआरसी–सीएए विरोधी आंदोलन पर मोदी ने इस टिप्पणी से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की कि विरोध करने वालों को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। लेकिन यह दांव भी नहीं चला। लोगों ने वोट करते समय रघुबर दास सरकार के कामकाज के अलावा केंद्र के मुद्दों को भी नकारा। झारखंड के आदिवासियों में रघुबर सरकार की नीतियों को लेकर गुस्सा था। उनकी हजारों एकड़ जमीन एक पूंजीपति घराने को पावर प्लांट लगाने के लिए दी गई और उनके विरोध को कुचल दिया गया। काश्तकारी कानून में बदलाव को भी पसंद नहीं किया गया। सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की बहाली का मुद्दा बार–बार उठता रहा। हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति में दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को नौकरी मिलने का मामला खूब उछला। राज्य लोकसेवा आयोग की एक भी परीक्षा पिछले पांच सालों में नहीं हो पाई है। पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं पर लाठी चार्ज की घटनाओं से भी राज्य सरकार के प्रति नाराजगी फैली। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के अहंकारपूर्ण और तानाशाही वाले बर्ताव से सभी पार्टियों के, यहां तक कि खुद बीजेपी के नेता भी नाराज थे। इसके चलते पार्टी को बड़े पैमाने पर अपने ही नेताओं के असहयोग और भितरघात का सामना करना पड़ा। चुनाव से पहले दूसरे दलों से पांच विधायक बीजेपी में आए। बीजेपी ने इन्हें टिकट दिया तो वहां के बीजेपी नेता बागी हो गए। सरयू राय जैसे पुराने नेता ने भी विद्रोह का रास्ता अपना लिया। कई सीटों पर बागी उम्मीदवारों ने पार्टी का खेल खराब किया। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के महागठबंधन ने समय से सीटों का बंटवारा किया और मुख्यमंत्री पद को लेकर सहमति कायम कर ली।

पिछले चुनाव में इन्होंने अलग–अलग रहकर लड़ने का नतीजा देख लिया था और उससे सबक लेकर पहले से ही सचेत हो गए थे। झारखंड में 26.3 प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है और 28 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। विपक्ष ने जेएमएम के आदिवासी नेता हेमंत सोरेन को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने लगातार दूसरी बार गैर–आदिवासी रघुबर दास को ही इस पद के लायक समझा। चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिला। इस क्रम में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बाद पांचवां राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गया। वक्त आ गया है कि पार्टी जनता का इशारा समझे और इस अति आत्मविश्वास से बाहर निकले कि उसकी हर नीति पर पूरे देश में आम सहमति है।

चिंताजनक

आसू। अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब हरियाणा के एक गाँव में जाटों की प्रताडना और उपेक्षा से आहत दलितों ने सामूहिक रूप से मुसलमान होने का फैंसला लिया. उत्तरप्रदेश के आजम खघन से डरे लोगों ने अपने मकान दुकान तोड़े जाने के भय से इस्लाम कबूलने की बात की. कसाब, अफजल गुरु और मेमन की फाँसियों ने तो जैसे भारतीय धर्मनिरपेक्ष ढाँचे को चरमरा ही दिया. औरंगजेब के नाम की सड़क का नाम बदल कर श्रद्धेय डा. अब्दुल कलाम का नाम देना तो जैसे अत्याचार की पराकाष्ठा ही हो गयी !! स्वयं उपराष्ट्रपति सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की अनदेखी और भेदभाव की बात सार्वजनिक रूप से बोलने पर मजबूर हो गये. बॉलीवुड के मसीहा और गणेश चतुर्थी पर आरती की थाल लिये दिखने वाले सलमान खान का खून खौल उठता है यदि दुर्दांत याकूब मेमन को फांसी दी जाती है।

संपादकीय

भारत की राजनीति

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रियंका गांधी को न उतारने के कांग्रेस के फैसले से एक बड़े तबके को निराशा हुई थी। कांग्रेस के भीतर से ही यह चर्चा उठी थी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में पार्टी प्रियंका गांधी को आगे ला सकती है। इस पेशकश से देश के उस वर्ग में उत्साह पैदा हुआ था जो इस लोकसभा चुनाव को एक वैचारिक लड़ाई के रूप में देख रहा था और मान रहा था कि सर्वसमावेशी चरित्र वाली कांग्रेस ही बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति को चुनौती दे सकती है। चूंकि मोदी बीजेपी का प्रतिनिधि चेहरा हैं तो उनके बरक्स विपक्ष के भी किसी शीर्ष नेता को ही उतारा जाना चाहिए, ताकि वैचारिक संघर्ष को एक धार मिल सके। जब दोनों खेमों के बड़े नेता एक–दूसरे के सामने खड़े होंगे तो दो भिन्न सिद्धांत बेहतर ढंग से सामने आएंगे। इससे पूरे देश की जनता के सामने परिदृश्य साफ होगा और मतदान को लेकर एक मजबूत फैसले तक पहुंचने में उसे सहूलियत होगी। लेकिन पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने नई जमीन तोड़ने के बजाय लीक पर चलना ही पसंद किया।

भारत की संसदीय राजनीति में ताकतवर नेता के खिलाफ विरोधियों की ओर से कमजोर उम्मीदवार देने का चलन सा बना हुआ है। हर पार्टी इस अघोषित नियम का पालन करती है, शायद इसलिए कि अपनी सीटें खोने का जोखिम वह नहीं लेना चाहती। हालांकि इसे सिद्धांत का आवरण दिया जाता है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक अपने निर्णय के लिए राहुल ने नेहरूवादी परंपरा का हवाला दिया। उनका तर्क था कि नेहरू अपने विरोधियों जैसे राममनोहर लोहिया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का काफी सम्मान करते थे और चाहते थे कि वे संसद में रहें। तो क्या माना जाए कि राहुल भी मोदी के सम्मान के लिए उन्हें संसद में भेजना चाहते हैं?

लंदन में हुए एक शोध में कहा गया है कि किशोरावस्था में बुलीइंग का शिकार होने वालों में से 40 प्रतिशत के मनोरोगी होने की आशंका रहती है।

चिढ़ाना-मजाक उड़ाना

अनुप

बचपन में अपने साथ हुई बुलीइंग को भले ही हम भुला दें पर इसका नकारात्मक प्रभाव वयस्क होने के बाद भी देखा जा सकता है। बुलीइंग का मतलब है दबाव डालना या धौंस दिखाना, चिढ़ाना–मजाक उड़ाना या पीटना। लंदन में हुए एक शोध में कहा गया है कि किशोरावस्था में बुलीइंग का शिकार होने वालों में से 40 प्रतिशत के मनोरोगी होने की आशंका रहती है। मनोरोग के लक्षण प्रायरू तब उभरते हैं जब बच्चे 20–25 की उम्र में पहुंचते हैं। मनोरोगों में डिप्रेशन प्रमुख होता, जिसके चलते उन्हें नौकरी मिलने में दिक्कत होती है।

लैंकस्टर यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट स्कूल के अर्थशास्त्र विभाग में असोसिएट रह चुकीं एम्मा गॉरमैन ने अपनी इस स्टडी के लिए यूके के 7000 छात्र–छात्राओं को चुना। उन्होंने पहले उनसे तब बात की जब वे 14–16 की उम्र के थे। उसके बाद तकरीबन दस वर्षों तक उनसे समय–समय पर बातचीत की गई। गॉरमैन ने पाया कि टीनेजर्स की बुलीइंग मुख्यतरू स्कूल में होती है। लड़कियां भावनात्मक बुलीइंग का शिकार होती हैं, जैसे अपने ग्रुप से अलग–थलग कर दिया जाना, दोस्तों का बातचीत बंद कर देना या किसी बात को लेकर चिढ़ाना। दूसरी तरफ लड़के हिंसक बुलीइंग का शिकार ज्यादा होते हैं। यह अध्ययन भले ही विदेश में किया गया हो, पर दुनिया भर के बच्चों पर लागू होता है। विकसित देशों में बच्चों को कानून के तहत कई अधिकार मिले हुए हैं। इसलिए उन्हें मां–बाप या किसी और रिश्तेदार की बुलीइंग का शिकार नहीं होना पड़ता है। भारत में तो बच्चे सबसे ज्यादा पिता, चाचा या दादा की बुलीइंग का शिकार होते हैं। हमारे यहां संयुक्त परिवारीय मूल्य के तहत पारिवारिक अनुशासन का अच्छा–खासा आतंक रहा है। न सिर्फ परिवार बल्कि पास–पड़ोस की आंखें भी एक बच्चे के पीछे लगी रहती हैं। एक बच्चे के 'भले' होने का अर्थ है कि वह चुपचाप बड़ों की आज्ञा मानता रहे। अगर बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी करता है या अपनी आंखों से दुनिया देखने की कोशिश करने लगता है तो उसे मौखिक उपदेश से लेकर पिटाई तक झेलनी पड़ती है। उसे वह बनने की कवायद करनी पड़ती है जो घर के लोग चाहते हैं।

इस तरह उसकी इच्छा, कल्पनाशीलता और सर्जनात्मकता की बलि चढ़ जाती है। घर में आमतौर पर संवाद का माहौल नहीं रहता। मां–बाप बच्चों से बात नहीं करते। उसकी शिकायतों, उसकी परेशानियों को जानने की कोशिश नहीं करते। ऐसे में बच्चे के भीतर बहुत–सी बातें दबी रह जाती हैं, जो धीरे–धीरे कुंठा का रूप ले लेती हैं। बड़ा होने पर ऐसे लोग कोई पहलकदमी नहीं कर पाते। वे नए विचार खोजने के बजाय बस आदेश का पालन करते हैं। इनमें से कई ऊपर से भले ही शांत दिखते हों पर कई मौकों पर वे उग्र हो जाते हैं। ऐसे ही कुंठितों में से कुछ बलात्कारी भी निकलते हैं। परिवारों और स्कूलों में संवाद का माहौल बनना चाहिए ताकि बच्चों का स्वाभाविक विकास हो सके।

सूडोकु नवताल-5197

सरल

2		8	5	1	9	6		7
					8			1
		7	4	6		8		9
3	2				7			8
1		9		4		7		5
4			2				9	3
6		3		5	1	9		
8			3					
7		1	9	2	6	3		4

Jagrutidaar.com, Bangalore

सूडोकु नवताल -5196 का हल

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

7	1	9	8	5	3	2	6	4
4	5	3	6	2	9	7	1	8
6	2	8	4	7	1	9	5	3
9	8	2	7	3	5	1	4	6
1	3	6	9	4	8	5	7	2
5	7	4	1	6	2	8	3	9
8	4	7	5	9	6	3	2	1
3	6	1	2	8	7	4	9	5
2	9	5	3	1	4	6	8	7

अपना ब्लॉग

विद्यादान सबसे बड़ा दान, करें इसमें निवेश

प्रणव प्रियदर्शी। हाल में जेएनयू के छात्रों के जिस आंदोलन ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह फीस बढ़ोतरी को लेकर था। देश के दूसरे विश्वविद्यालयों के स्टूडेंट्स ही नहीं, आम युवाओं और उनके अभिभावकों के बीच भी जेएनयू से जुड़े दूसरे मसलों पर भले नाराजगी हो, इस चिंता पर उनके बीच सहमति थी कि आखिर महंगी होती शिक्षा सामान्य घरों के बच्चों तक कैसे पहुंचेगी। ये बच्चे शिक्षा का अपना अधिकार कैसे हासिल कर पाएंगे? एक तरफ बच्चों के जायज हक और दूसरी तरफ सरकार की सीमाएं। इनकम शेयर अग्रीमेंट का मॉडल हमारे दौर की इस बड़ी दुविधा को दूर करता है। भारत के लिए यह जरूर अभी नई चीज है, लेकिन अमेरिका और अन्य जगहों पर यह योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। यहां कर्ज वापसी सीधे कमाई से जुड़ती है सो यह बैंकों के स्टूडेंट लोन जैसा नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब होता है बच्चों से यह कहना कि पढ़ाई के खर्चे की चिंता आप मत करो, बस मन लगाकर पढ़ो। आपकी फीस या और भी जरूरी खर्चे जो आप वहन नहीं कर सकते, हम उठाएंगे। बाद में जब आप जॉब में आ जाओ तब वे पैसे हमें धीरे–धीरे सूद सहित वापस कर देना।